SHRI TINDIVANAM G VENKATRAMAN: Mr. Chairman, Sir, regarding Tamil Nadu, he has not answered.

MR. CHAIRMAN: The main question was about Pondicherry and Pondicherry is still not a part of Tamil Nadu.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: When the hon. Member, Mr. Madhavan has put a question regarding Tamil Nadu, the hon. Minister has responded to it. ..(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You put a separate question for Tamil Nadu. I will allow it. (*Interruptions*) It is spread out in Pondichery. It is spread out in Tamil Nadu. It is spread out Kerala. It is speard in Andhra Pradesh.

श्री चतुरानन मिश्र : चर्चा हो रही है कि साउथ के साथ डिसक्रिमिनेशन हुआ । इसलिये मंत्री महोदय के लिये यह उचित होगा कि सारे भारत में कैसे डिस्ट्रिब्यूशन हुआ, इसके बारे में सारी सूचना आप सभा पटल पर रख दें ताकि इस बारे में सब को जानकारी हो सके कि अगर साउथ के डिसक्रिमिनेशन हुआ हैं तो नार्थ के साथ क्या हुआ, हमारे बिहार में किरोसीन आयल का क्या हुआ, ये सारी बातें आप यहां रख दें ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: We have a genuine grievance that we have been discriminated against in India.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you lay on the Table of the House the details as to how much of Kerosene you have allotted to different States.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH: I was only trying to be helpful to hon. Members by providing information If they do not want the information in the spirit in which I want to give them, I would only request that the question should be limited to the area for which it was asked. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: If you can answer for Kerala, why not for Tamil Nadu? Why should there be a discrimination?

MR. CHAIRMAN: Don't argue. Question No. 122.

तिलहनों का उत्पादन

***122. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य तेलों की मांग 1990-91 के वर्ष में आपूर्ति की अपेक्षा 10 लाख टन अधिक आंकी गयी हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष देश में तिलहनों का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक हुआ है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच हैं कि इस वर्ष कुछ तिलहनों का निर्यात किया गया हैं और यदि हा, तो उनकी मात्रा कितनी थी और इस निर्यात की अनुमति दिये जाने के क्या कारण थे ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण-पत्र

(क) वर्ष 1990-91 के लिए रबी तिलहन उत्पादन का अनुमान लगाना अभी सभव नहीं हैं । अतः मांग और स्वदेशी आपूर्ति के बीच के अन्तर का अनुमान लगाना असामयिक होगा । 1990-91 के तेल वर्ष के लिए खाद्य तेलों की मांग 60.26 लाख मीटरटन होने का अनुमान हैं ।

(ख) 1989-90 में 167.5 लाख मीटरीटन तिलहन उत्पादन होने का अनुमान है। चालू वर्ष के लिए उत्पादन का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

(ग) अप्रैल अक्तूबर, 1990 के दौरान तिलहनों का अनुमानित निर्यात निम्नलिखित था:

जिन्स	मात्रा मीटरी टन	मूल्य (करोड़ रु. में)
तिल	31600	32.78
एच.पी.एस. मूंगफली	5659	6.61
रामतिल बीज	6920	8 40

एच. पी. एस. मूंगफली और तिल बीजों के निर्यात का बहुत मूल्य है इनसे वर्तमान में होने वाली वसूली से, इन बीजों के निर्यात में होने वाली खाद्य तेल से जितनी हानि होती है उससे 6 गुणा अधिक मात्रा में आयात से उपलब्धि हो जाती है। रामतिल बीज का पक्षी आहार के रूप में निर्यात नाम मात्र किया जाता है। इन निर्यातों ने अधिमत तेलों की देश के भीतर उपलब्धता को कोई अधिक प्रभावित नहीं किया है। दूसरी ओर, इन निर्यातों से हम घरेलू खपत को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों से आयात कर सके हैं।

डा० जितेन्द्र कुमार जैन : उपसभापति महोदय, यह प्रश्न चौधरी देवीलाल के महकमे से पूछा गया है और चौधरी देवीलाल मजदूर हैं खरी बात करने के लिए लेकिन जो जवाब दिया गया उसमें खरी-खरी बात नहीं कही गई है। सच यह है कि हम आयल सीड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और आयल हम बाहर से इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। हो क्या रहा है, यह मैं आपके माध्यम से चौधरी देवीलाल जी को बताना चाहता हूं। जब सीजन आता है तो उस समय हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें फोरेन एक्सचेंज कमाना है और जब सीड का समय आता है तो हम आयल इम्पोर्ट करते हैं हमें क्योंकि कमी को पूरा करना है। इस आयात और निर्यात के टाइमिंग की वजह से किसान को नुकसान होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नारियल के तेल के विषय में हमारी सरकार की प्लानिंग है कि हम बड़ी भारी तादाद में श्रीलंका से मंगाया है। मार्च के महीने में यह हालत होगी कि पोर्ट पर इम्पोर्ट पर तेल खत्म होगा और यहां की फसल भी खत्म होगी। इससे यहां का किसान जो नारियल पैदा करता है उसको नारियल का उचित दाम नहीं मिलता है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस बात की कोशिश की जा सकती है, कि डोमेस्टिक मार्किट सिस्टम बनाया जाए जिससे कि आयल सीड पैदा करने वाले किसानों को मार्किट में मिलने वाली कीमत का मुकाबला इम्पोर्टेड आयल के दाम से न होगा?

श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपको जवाब दिया गया है वह सही है। सही इसलिए है कि जो खरीफ में आपने कहा है कि कुछ वृद्धि हुई है मगर मूंगफली के उत्पादन में कमी होने से खरीफ में काफी घाटा हुआ है। रबी का जो मौसम है वह तो अभी आने वाला है, जब यह आएगा तभी पता चलेगा। कल किसने देखा है। अभी भी ठंड पड़ने से नुकसान हो सकता है। आज यह अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं या जो हमारी ट्रेडिशनल पोजीशन है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत थोड़ा एच. पी. एस. मूंगफली बाहर भेजते हैं और जो हम नाइजर भेजते हैं उसका यूज हमारे देश में बहुत कम होता है। वह अमरीका जाता है। इसमें जो हम तेल मंगाते हैं वह हम 6 गुना ज्यादा तेल मंगवा सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता है क्योंकि जितना हम भेजते हैं उसमें एक टन में से 400 किलो तेल निकलता है इसमें 6 गुना ज्यादा बाहर से तेल मंगवा लेते हैं। इससे देश को कोई नुकसान नहीं होता है।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN Sir, because I spoke in Hindi, probably the hon Minister did not understand my question My question is, do you consider a plan to set up a domestic market management system to bring adjustments between imports and exports? That is all. I repeat. Are you thinking of a domestic market management system?

श्री जयन्तीलाल वीरचंदभाई शाह : सभापति जी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सवाल है वह हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है । इसलिए मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता ।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, I wish to bring the attention of the Government a visit of the former Prime Minister Shri V. P. Singh to Kerala where he had declared that coconut would also be considered as an oilseed crop But the subsidy that is being given to grounnut, gingelly and mustard, being considered as oilseed crops, is not being given to the coconut-grower. What is the Government doing about it? Why is not the Government implementing a promise made to the people of India?

श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : इसका सवाल तो अलग ही पूछा गया था । मगर बात यह है कि तीन महीने पहले कोकोनट को हमने इस सिस्टम में रखा है । इसके लिए कोकोनट का एक बोर्ड भी बनाया है । पहले से काम करता था मगर तीन महीने से कोकोनट को हमने एग्रीकल्चरल कमोडिटी जाहिर कर दिया है । एग्रीकल्चरल कमोडिटी जाहिर करने के पीछे कोकोनट ग्रोअर्स को जो लाभ मिलेगा वह लाभ हम देने वाले हैं । जैसे 9 चीजों के लिए हमने टैक्निकल मिशन बना दिए हैं इसके लिए हमारा जो कोकोनट का बोर्ड बना है उसमें ज्यादा प्रावधान करके हम कुछ करने वाले हैं ।

श्री सभापति उनका सवाल है You are giving 30 per cent subsidy. Will you give it for coconut also?

श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : दे तो दे रहे हैं मगर उससे ज्यादा कुछ करने वाले हैं ।

MR. CHAIRMAN: Will you give it for coconut?

श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : कोकोनट का जो बोर्ड है, प्लांटेशन के लिए सभी के लिए वह कुछ कर रहा है । इससे हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं ।

श्री सभापति : उनका स्पेसिफिक प्रश्न है आप जो ग्रायलसीड्स को दे रहे हैं वह सब्सिडी क्या कोकोनट को भी देंगे । उनका इतना सा प्रश्न है ।

श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : इसका बोर्ड जो है ..

श्री सभापति : वह तय करेगा ।

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : यह सब्सिडी का जो डिसिजन है .. (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : मिनिस्टर जैन को चाहिए कि कोकोनट का बोर्ड बना ले ।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, the Board does not decide it. The Government has to decide it.

DR JINENDRA KUMAR JAIN: Mr. Chairman, Sir, I am not asking for anything for the people sitting here I am asking for the benefit of the poor farmers of this country. Please don't laufgh at it. My demand is, once this promise was made by the Prime Minister directly to the people in a big meeting in Kerala, the Government should say when they will implement this. They should say whether they are doing it or not. I want to know from the Government when it will be implemented.

MR CHAIRMAN: The promise to give 30 per cent subsidy?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: You should let me have the answer from the Government, Sir, as to when they will implement this decision. The Prime Minister cannot declare anything without deciding.

MR. CHAIRMAN: When will you implement the decision taken by Mr. V. P. Singh?

श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : ऐसा है कि तीन महीने पहले वह घोषित की गयी है और 4 दिन पहले केरल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट आई है । इसमें ज्यादा मदद देने का प्रावधान किया गया है । यह हमारे पास आई है अब हम उस पर विचार कर रहे हैं ।

डा० जितेन्द्र कुमार जैन : जवाब नहीं दे रहे है ।

श्री सभापति : वे जवाब नहीं दे सकते ...(व्यवधान)

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, coconut is not only grown in Kerala, but it is also grown in Karnataka.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है

the demand of edible oil for 1990-91 is estimated to be 60.26 lakh tonnes.

उन्होंने एक्सपोर्ट की जो फ़िगर्स दी है यहां पर कि सीसामम ग्राउडनट और साइजर शीट का 34,199 टन है और उसका फ़ारेन एक्सचेंज मिलता है 47.79 करोड़ । मगर उन्होंने यह भी बताया है कि जो इम्पोर्ट होता है उससे 6 गुना ज्यादा इम्पोर्ट होता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट के लिए हम कितना फ़ारेन एक्सचेंज यूटिलाइज करते हैं और इंपोर्ट में हमारा कितना पैसा खर्च होता है ? चौधरी देवी लाल ने पिछले साल किसानों की उपज के दाम बढ़ाकर किसानों को राहत देने की कोशिश की । भारत का किसान होने के नाते मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । मगर आयल सीड का जो मसला है यही हमारे देश के सामने सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मसला है । दो साल पहले हम 1500 करोड़ रुपया एडीबुल आयल के इम्पोर्ट पर खर्च करते थे ? मैं अब यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कितना पैसा फ़ारेन एक्सचेंज के रूप में एडीबुल आयल्स के इम्पोर्ट पर खर्च हो रहा है । जब हमारे पास ही नहीं है तो हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है ।

मेरे क्वेश्चन का "बी" पार्ट यह है कि यह जो किसानों की चीजों के दाम डिक्लेयर करते हैं आयल सीड्स के या अन्य के तो यह सब मिडिलमैन एजेंसीज खा जाती हैं । हमने कई दफ़ा इस सदन में यह सवाल उठाया है कि किसानों को पीसने वाली, एक्सप्लायट करने वाली जो मिडिलमन एजेंसिज हैं उनका आप क्या बंदोबस्त करने जा रहे हैं । यह सब तो दलालो के घर चला जाता है आप जो भाव आदि बढ़ा देते है और जब मौसम आता है तो किसानों की जेब मे बहुत कम जाता है इसके बारे मे क्या ठोस कदम उठाने वाले हैं , आप उप प्रधान मंत्री भी हैं, किसान भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं चौधरी साहब इस नाते से मैं आपसे यह जानना चाहता हूं ।

उप-प्रधान मंत्री, कृषि और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल): अब मुझे जवाब देना ही होगा । स्पीकर साहब हमारी कोशिश यह है ...

एक माननीय सदस्य : चेयरमैन साहब ।

श्री देवीलाल : चेयरमैन साहब जबान पर चढ़ा हुआ है। यह आज पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन हुआ है ।

सवाल यह है कि हम तेल पैदा करने वाली चीजों का भाव बढाएं और रु. 115 पर क्विंटल सरसों का इसी वास्ते भाव बढ़ाया है। उन्हें बिजली और पानी की पूरी सहूलियत देंगे ताकि हमें इम्पोर्ट न करना पड़े। आप तसल्ली रखें, यह दिन-ब-दिन बढता रहेगा। इसीलिए हमने कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया है। उसकी रिपोर्ट भी आई है। उसी के आधार पर और ज्यादा मदद करेंगे।

उसी के साथ-साथ हम तेल के संबंध में, कोकोनट के संबंध में सब्सिडी भी पूरी देने की कोशिश करेंगे, पर उनकी रिपोर्ट आ लेने दें।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मिडलमैन एजेंसी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। जो दलाल खा जाते है किसानो का, उसके बारे में आप क्या इंतजाम करने जा रहे हैं?

श्री देवी लाल : दलालों का इंतजाम हम हर जगह कर रहे हैं। हम हर मामले में मार्केट इंटरवेंशन कर रहे हैं।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहुंगा—उन्होंने स्टेटमेंट दी है एच.पी.एस. मूंगफली के लिए—तो मैं जानना चाहंगा कि आज के दिन एन. डी. डी. बी. के पास कितना मूंगफली के तेल का स्टाक है और दिन प्रतिदिन जो उनका मूंगफली के तेल का दाम बढता ही जा रहा है, तो वह कम करने के लिए एन. डी. डी. बी. क्या एक्शन लेने जा रही है?

श्री जे० वी० शाह : एन डी. डी. बी. के पास कतना तेल का स्टाक हैं, वह तो मेरे पास जानकारी आज नही है साहब. क्योंकि वह तो इस प्रश्न से उठता नही है।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : वह तो आपने दिया है।

श्री जे०वी० शाह : नहीं, एन० डी०डी० बी. के पास कितन स्टाक हैं, वह चीज तो आज मैं नहीं बता सकूंगा क्योंकि यह जानकारी आज मेरे पास नहीं है।

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा—आज जो उत्तर आया हैं, उसमे कहा गया है कि मांग और स्वदेशी आपूर्ति के बीच के अन्तर का अनुमान लगाना असामयिक होगा। 1990–91 के तेल वर्ष के लिए खाद्य तेलो की मांग 60.26 लख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

मैं जानना चाहता हूं कि जब आप यह कहे हैं कि खाद्य तेलों की मांग 1990–91 के लिए 60.26 लाख मीट्रिक टन हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह ठीक है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहुंगा कि 1990–91 के लिए क्या लक्ष्य रखने गया था? उस उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कितना अंतर आ रहा हैं और उस अंतर को ध्यान में रखते हुए सरकार उस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? नम्बर एक।

उसी के साथ (ख) यह होगा कि सरकार इस बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन को बढाने के लिए क्या-क्य कदम उठाने जा रही हैं, ताकि किसानों का शोषण भी न हो, प्रोडक्शन भी हो जाए और इम्पोर्ट जो किया जाता है, उसमें भी कमी आ जाए? इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाने का फ़ैसला किया है? इसके साथ ही (स)...

श्री सभापति : इतना न जोड़ें भाई।

श्री राम नरेश यादव : : यह तो (ए) हुआ, (स) यह है कि अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम बिचवइयों द्वारा शोषण नही होने देंगे। महोदय, स्पष्ट है कि अभी पिछले दिनों धान की फ़सल की [illegible] तय हुई है।

श्री सभापति : अभी प्रश्न कर लो।

श्री राम नरेश यादव : मैं वही पूछने जा रहा हूं। लेकिन रु. 160 और रु. 165 क्विंटल के हिसाब से किसान मजबूर हुआ है हमारे पूरे प्रदेश में उस धान को बेचने के लिए, यह शोषण हो रहा है। कहीं पर कोई खरीद केन्द्र की स्थापना नहीं हुई है, ताकि सपोर्ट प्राईस किसानों को मिल सके।

इसको ध्यान में रखते हुए आने वाली जो रबी का तिलहन है, उसका सही दाम किसानों को मिल सके और उनका शोषण न हो सके, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री जे वी० शाह : ऐसा है साहब कि तिलहनों को जो उत्पादन पहले हो रहा था, पिछली पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत काम किया है। तो 1985-86 से लेकर वह 1-9 मिलियन हैक्टर में जो उसका काम हो रहा था, उससे बढ़कर 1989 में वह 22.97 मिलियन हैक्टर पर गया है। हालांकि उस अवधि के दौरान उत्पादन भी 10.83 मिलियन था, उससे बढ़ कर वह 16.74 मिलियन हो गया है और 18 मिलियन सबसे अधिक उत्पादन 1989 के दौरान हुआ है और उसके लिए बहुत मेहनत भी की गई है। 1985 में जो 570 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की जो उपज हुई थी, उसको लेकर 729 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर और 1989-90 में 824 प्रति हैक्टेयर की उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो तीनों मसलों में तिलहनों के बारे में बड़ा अच्छा काम हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि किसानों को पूरा काम नहीं मिलता है, मैं जानता हूं कि जो सपोर्ट प्राइस हमने मक्की की है, उसकी की है कि किसानों को अच्छा भाव मिले, मगर मार्केट की पोजीशन ऐसी है, तो उससे भी किसानों को बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। आज भी मिल रहा है, यह मैं आपको बताना चाहता।

श्री सभापति : उनका कहना यह है कि अभी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए जो दाम आपने मुकर्रर किया था, उतना नहीं मिल पाया है। आप बताइए कि आप क्या बरकोब करेंगे कि सपोर्ट प्राइस पर खरीद हो जाए।

श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह : वह तो आप गेहूं के लिए कह रहे हैं या तिलहन के लिए? सवाल तो तिलहन का है, आप अनाज की बात कह रहे हैं तो मैं जवाब कहां से दे सकूंगा।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि आपने कहा कि शोषण नहीं हो रहा है, जिस तरह का शोषण हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आगे से शोषण नहीं होगा, इसको आप एश्योर कर दीजिए।

श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : तिलहन वाले का शोषण तो आज भी नहीं हो रहा है क्योंकि बड़ा अच्छा भाव मिल रहा है। आप बात कर रहे हैं अनाज वालों की तो उसके लिए भी ख्याल रखें कि उनका शोषण न होने पाए।

श्री राम नरेश यादव : माननीय सभापति, मेरे सवाल का उत्तर तो नहीं आया... (**व्यवधान**)... मैंने पूछा था कि 1990-91 के लिए क्या अनुमानित लक्ष्य रखा गया था उसको ध्यान में रखते हुए आप बताएं कि कितना अंतर आ रहा है? मैं लक्ष्य की बात पूछ रहा हूं। उसका उत्तर तो आए।

श्री सभापति : अंतर नहीं बता सकते, टार्गेट तो बता सकते हैं आप?

श्री राम नरेश यादव : मैं टार्गेट पूछ रहा हूं, तिलहन उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया था?

श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : इसका टार्गेट तो 18 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जिसमें खरीफ 10 मिलियन टन और रबी का हमने 8 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है।

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: This Ministry has no integrted policy regarding the export and import of oil-seeds. Coconut is the backbone of Kerala's economy. And if I put a question about import and export of coconut I expect the Minister would rise and say, "It does not pertain to my Ministry". But ultimately the question is: What is the policy of this Government? When import or export of oils and oil-seeds products is done, are the concerned State Governments consulted, when such action is taken about oil-seeds and products of oil-seeds? I would like the Deputy Prime Minister to answer because it is a question which pertains to the entire policy of the Government.

MR. CHAIRMAN: I think, Mr. Sreedharan, you yourself were a Minister of Commerce, it does not come under the Ministry of Agriculture: it comes under the Ministry of which you were in charge earlier. It does not come under the Ministry of Agriculture.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: You have not got my question. The question is when a decision is taken to export or import oil-seeds or oil-seeds products, whether the Ministry of Agriculture consults the Ministry of Commerce or give directions to the Ministry of Commerce so that the oil-seeds of a particular State are not adversely affected.

MR. CHAIRMAN: Do you import or export oil? They don't You do it ..

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: When complaint was made that as a result of the import of conocnut oil the entire State was adversely affected, it was brought to the notice of the Agriculture Ministry also. What steps were taken to ask the Commerce Ministry not to do this anti-social activity?

MR. CHAIRMAN: Mr Sreedharan, you have said "also".

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: We did not permit it in V. P. Singh Government; it was a Ministry for the people, for the agriculturists.

Decline in the Room occupancy rate in the ITDC Hotels

*123. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the room occupancy rate in the ITDC Hotels has gone down this year as compared to that durmg the last three years;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken by the Marketing Division of the ITDC to counteract the low occupancy of foreign tourists?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SMT. USHA SINGH): (a) The average room occupancy of ITDC's 25 owned hotels has registered a decline of 7 per cent during the financial year 1990-91 (up to Nov. 90) as compared to the same period in 1989-90 and 1988-89 and a decline of 6 per cent as compared to 1987-88.

(b) The overall prevailing situation in the country and its adverse publicity abroad are the main reasons.

(c) The following steps have been taken by the Hotels Sales Division of the ITDC to improve the occupancy of foreign tourists:—

(a) Sponsoring familiarisation tours of foreign travel agents and travel writers to India.

(b) Aggressive marketing in Travel Trade Fairs like ITB Berlin ASTA FITUR WTM etc. and sales promotion in select countries abroad.

(c) Signing of special rate contract with foreign tour operators by offering incentives on Volume business to encourage group tourism.